जो आत्मशक्ति का अनुसरण करके संघर्ष करता है उसे महान विजय अवश्य मिलती है।–अज्ञात।

विचार-प्रवाह

देहरादून, शुक्रवार 14 जनवरी 2022

पेज थ्री
www.page3news.in

आम लोगों के लिए जीना मुश्किल

सरकार का यह फैसला 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद आया है, जिन्हें कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक और बीजेपी के लिए चिंताजनक माना गया।

मनोज शाह।।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद दीपावली से ऐन पहले सरकार ने इन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में क्रमशरू 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर कटौती की। इससे लोगों को तत्काल कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सरकार के इस कदम का वैसा उत्साहपूर्ण स्वागत नहीं हुआ, जैसी उम्मीद की जा रही थी। कारण संभवतः यह है कि आम लोगों के लिए इस फैसले को सरकार की संवेदनशीलता से जोड़कर देखना संभव नहीं हो पा रहा।

पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल कीमतों का लगातार बढ़ता बोझ आम लोगों के लिए जीना मुश्किल किए हुए था। मगर सरकार ने कभी यह संकेत नहीं दिया कि वह इसे लेकर चिंतित है या इसे कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। सरकार का यह फैसला 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद आया है, जिन्हें कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक और बीजेपी के लिए चिंताजनक माना गया। स्वाभाविक ही इससे यह संदेश गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित है और ताजा फैसला इसी चुनावी चिंता से उपजा है।

इसका मतलब यह माना गया कि इन राज्यों में चुनाव होते ही पेट्रोल और डीजल के भाव फिर ऊपर का रुख कर लेंगे। दूसरी बात यह कि पिछले कुछ समय में इनके दाम में जो असाधारण बढ़ोतरी हुई है, उसके मुकाबले यह कटौती बहुत कम है। 2021 की ही बात करें तो साल की शुरुआत से अब तक पेट्रोल और डीजल के भाव करीब 28 रुपये और 26 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। इस मुकाबले 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती को राहत माना भी जाए तो कैसे? खासकर तब, जब इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों से ज्यादा बड़ी भूमिका एक्साइज ड्यूटी की हो।

ताजा कटौती के बाद भी पेट्रोल पर 27.90 रुपये और डीजल पर 21.80 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान लगने वाली ड्यूटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हालांकि आज के हालात और चुनौतियों की तुलना पिछली सरकारों के कार्यकाल से नहीं की जा सकती। लेकिन पेट्रोल और डीजल के ऊंचे भाव न केवल शहरों और गांवों के आम वाहनधारकों को प्रभावित करते हैं बल्कि फसलों की सिंचाई और माल ढुलाई का खर्च बढ़ाकर आम तौर पर महंगाई का स्तर बढ़ा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार पेट्रोल–डीजल के दाम में और कमी लाने पर विचार करे।

बड़ा दुख

अशोक वोहरा। बकरे के लिए कोई काम तो था नहीं। वह दिन भर इधर–उधर घूमकर हरी–हरी घास चरता रहता। खा पीकर वह काफी मोटा तगड़ा हो गया था। यह देखकर बैल सोचते कि इस बकरे के मजे हैं। कुछ करता–धरता तो है नहीं और सारा दिन इधर–उधर घूमकर खाता रहता है। इधर, बकरा बैलों की हालत देखता तो उसे भी बड़ा दुख होता कि बेचारे सारा दिन हल में जुते रहते हैं और मालिक है कि इनकी ओर पूरी तरह ध्यान नहीं देता। वह बैलों को कुछ सलाह देना चाहता था, जिससे इनका कुछ भला हो। एक दिन दोनों बैल खेत जोत रहे थे। बकरा भी वहीं खेतों के पास घास चर रहा था। दोनों बैलों को खेत जोतने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वे दोनों हांफ रहे थे। यह देखकर बकरा मूर्खतापूर्ण स्वर में बोला– "भाइयो, तुम दोनों को दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है।

संपादकीय

यूरोपीय देशों की मुश्किल

डेमोक्रेसी समिट के जरिए अमेरिका ने जता दिया कि वह किन देशों को साथ लेकर चलना चाहता है और उसकी व्यापक वैश्विक रणनीति चीन और रूस को अलग–थलग करने की है। जाहिर था कि रूस और चीन इसका कूटनीतिक रूप से जवाब देंगे। चीन ने जहां इस मामले में कई सारे बयान दिए, वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी तेज कर दी। रूस चाहता है कि जिस तरह से बाइडन ने डेमोक्रेसी समिट के जरिए अपना प्रभाव क्षेत्र निर्धारित किया है, उसी तरह यूक्रेन के मामले में यूरोप के देश वादा करें और तय करें कि पूर्वी यूरोप के इलाकों पर रूस के प्रभाव को वे मान्यता दे रहे हैं। यह एक जटिल समस्या है क्योंकि सीमा पर एक लाख से अधिक सैनिक तैनात करने के बाद बिना किसी आश्वासन के रूस का पीछे हटना उसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि अगर वह यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया नए सिरे से एक तरह के शीतयुद्ध में प्रवेश करेगी। इस शीत युद्ध में एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश होंगे तो दूसरी तरफ होंगे चीन और रूस। डेमोक्रेसी समिट के जरिए अमेरिका ने जता दिया कि वह किन देशों को साथ लेकर चलना चाहता है और उसकी व्यापक वैश्विक रणनीति चीन और रूस को अलग–थलग करने की है। जाहिर था कि रूस और चीन इसका कूटनीतिक रूप से जवाब देंगे। चीन ने जहां इस मामले में कई सारे बयान दिए, वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी तेज कर दी। रूस चाहता है कि जिस तरह से बाइडन ने डेमोक्रेसी समिट के जरिए अपना प्रभाव क्षेत्र निर्धारित किया है, उसी तरह यूक्रेन के मामले में यूरोप के देश वादा करें और तय करें कि पूर्वी यूरोप के इलाकों पर रूस के प्रभाव को वे मान्यता दे रहे हैं।

बाइडन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि रूस ने अगर यूक्रेन को परेशान किया तो रूस को कूटनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने फिलहाल यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर रखे हैं।

खेमेबंदी तेज हुई

जे सुशील।।

रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद से पश्चिमी देशों, अमेरिका और रूस के बीच तनाव का माहौल है। ग्रुप सात देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के विदेश मंत्रियों ने यूरोप में हुई बैठक के बाद रूस को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन की सीमा पर तनाव बरकरार रखता है या उस पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये गंभीर परिणाम क्या होंगे, इसका जिक्र ग्रुप सात देशों के बयान में नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि ग्रुप सात रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन से दो घंटे विडियो कॉल पर बात की। इसके बाद भी दोनों के बीच तल्खी बनी रही। बातचीत के बाद बाइडन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि रूस ने अगर यूक्रेन को परेशान किया तो रूस को कूटनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने फिलहाल यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर रखे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, रूस जनवरी या फरवरी तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है। फिलहाल इस सैनिक जमावड़े को लेकर यूक्रेन में अफरातफरी का माहौल है और यूरोपीय देश भी

इससे काफी चिंतित दिख रहे हैं। असल में, इस पूरे मामले को दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो रूसी तर्क है। इसके अनुसार यूक्रेन हमेशा से रूस का हिस्सा था, जो उससे अलग हो गया। वैसे, सोवियत रूस के विघटन के बाद जब यूक्रेन अलग हुआ तो वहां अमूमन रूस समर्थक सरकारें ही बनीं। 2014 में जब सरकार बदली तो उसने यूरोप और पश्चिमी देशों से मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी, जो रूस को नागवार गुजरी है।

रूस ताकत के जोर से यूक्रेन की इस कथित गलती को ठीक करना चाहता है। उसका तर्क है कि यूक्रेन से मित्रता के जरिए यूरोप उसे कमजोर करना चाहता है। रूस ने यूरोप के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह उसकी कुछ मांगों को मान ले तो सेना हटा ली जाएगी। इनमें से प्रमुख मांग यह है कि यूरोप इस बात की कानूनी गारंटी दे कि वह यूक्रेन को कभी भी नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनाएगा। साथ ही, यूक्रेन में पश्चिमी देशों के जो सैनिक हैं, वह संख्या अब नहीं बढ़ाई जाएगी। ये ऐसी मांगें हैं, जिन पर यूरोप का राजी होना मुश्किल है। इन शर्तों को मानने का अर्थ पूर्वी यूरोप में रूस के ऐतिहासिक प्रभाव पर मुहर लगाना होगा। यह इस मामले का एक पहलू है। इसका दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर अगर अमेरिका, चीन और रूस के संदर्भ में इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसकी कई बारीकियां समझी जा सकती हैं। इसी हफ्ते नौ और दस दिसंबर को अमेरिका ने वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट का आयोजन किया। इसमें दुनिया के कई देशों को बुलाया गया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने इसमें रूस और चीन को नहीं बुलाया। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि ये दोनों देश लोकतांत्रिक नहीं हैं। यह रूस और चीन के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका था क्योंकि अमेरिका ने इस बैठक में ताइवान और पाकिस्तान तक को बुलाया था। अमेरिका द्वारा आमंत्रित देशों की सूची पर जमकर हंगामा हुआ और सैनिकों के जमावड़े के प्रसंग को इस घटना के आलोक में भी देखा जाना चाहिए। इस सूची के आने और समिट होने तक चीन और रूस ने लगातार अमेरिका की आलोचना की। इसे अंतराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के लिए एक और मोर्चा खोलने के रूप में देखा जा सकता है।

सूडोकू नवताल- 5346

***** कठिनतम

7							4	
		5		3			7	
					8			2
					1	9		
	2						8	
		6	7					
1			4					
	9			2		5		
	8							1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकू नवताल -5345 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

चीन महाशक्ति के रूप में उभर रहा

मोहन। कोविड और उसके बाद के बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह साफ है कि चीन महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। रूस भी आज अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ रहने का मन बना चुका है। इसके साथ ही भारत के साथ भी रूस अपने संबंधों को बेहतर करने की लगातार कोशिशें कर रहा है, जिसके तहत पूतिन ने इस हफ्ते भारत की एक दिन की यात्रा भी की थी। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अभी तक भारत नहीं आए हैं। यह एक जटिल समस्या है क्योंकि सीमा पर एक लाख से अधिक सैनिक तैनात करने के बाद बिना किसी आश्वासन के रूस का पीछे हटना उसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि अगर वह यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया नए सिरे से एक तरह के शीतयुद्ध में प्रवेश करेगी। इस शीत युद्ध में एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश होंगे तो दूसरी तरफ होंगे चीन और रूस। वह अंतरराष्ट्रीय पटल पर चीन को अलग–थलग करने की कोशिश में लगा रहा है।